**केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा मध्य प्रदेश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा**

1854. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश में सूखे से उत्पन्न संकट का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा किन-किन स्थानों का किस-किस तिथि को दौरा किया गया;

(ख) अपने दौरे के दौरान अध्ययन-दल ने किन-किन स्रोतों से जानकारी एकत्र की है; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को प्रथम बार सूखे से उत्पन्न संकट की जानकारी कब दी थी?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पीने के पानी की परिस्थिति से पैदा संकट के बारे में केन्द्र को सितम्बर, 1989 के अन्तिम सप्ताह में, पहली-बार अवगत कराया। इसके बाद दिसम्बर, 1989 में एक ज्ञापन दिया गया। एक केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा 28 तथा 30 दिसम्बर, 1989 के मध्य राज्य का दौरा किया गया। अपने दौरे के दौरान अध्ययन दल तीन समूहों में विभाजित हो गया और प्रत्येक समूह ने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा किया। अन्य बातों के साथ-साथ दल ने राहत कार्यों और राजगढ़, दुर्ग, राजनन्द गांव, बिलासपुर, जबलपुर, रामसेन, सागर, भोपाल और ग्वालियर सम्भाग के कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति योजनाओं को देखा। अपने दौरे के दौरान केन्द्रीय अध्ययन दल ने किसानों, फ़ील्ड स्टाफ़, जनता और उनके प्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों और अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जानकारी एकत्र की।

**ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लश के शौचालयों के निर्माण के लिये किया गया आबंटन**

1855. श्री शिवप्रसाद चनपुरिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लश के शौचालयों के निर्माण के लिये कोई आबंटन किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : टू-पिट पोर फ्लश वाले स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का एक कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

**Direction to the States on Minimum Wages**

1856. DR YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether any directions have been issued to the States on minimum wages; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) Yes, Sir.

(b) Guidelines have been issued to the States to revise the minimum rates of wages for scheduled employments in a period not exceeding two years or on 50 points rise in Consumer Price Index, whichever is earlier States have also been requested to consider providing for a Variable Dearness Allowance linked with Consumer-Price Index alongwith the minimum rates of wages so that the unorganised labour is protected against rise in price level. The States have also now been advised not to fix minimum rate of wages in any employment below Rs. 15/- per day.